



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 5 मई, 2026

बैशाख 15, 1948 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार

नियुक्ति अनुभाग-4

संख्या 176/दो-4-2026-02-4003(002)/2-2025

लखनऊ, 5 मई, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-30

संविधान के अनुच्छेद 233 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुतियों के अनुसार उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2026

1-(एक) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (उन्नीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2026" कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1975, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये नियम 5 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:- नियम 5 में खण्ड (ग) का प्रतिस्थापन

स्तम्भ-1**(विद्यमान नियम)**

नियम 5-भर्ती का स्रोत- सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी:-

(ग) आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत अंतिम दिनांक को अन्यून सात वर्षों के लिये अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं में से सीधी भर्ती द्वारा:

परन्तु यह कि केवल ऐसे अधिवक्ता ही अर्ह होंगे जिन्होंने भर्ती के विज्ञापन के प्रकाशन वर्ष से पूर्व के अन्तिम तीन वर्षों में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष स्वतंत्र रूप से अन्यून निम्नलिखित मामलों का संचालन किया हो:-

(एक) अनारक्षित श्रेणियों के लिए 30;

(दो) इस नियमावली के अनुसार आरक्षण के हकदार अभ्यर्थियों के लिए 24;

स्पष्टीकरण:-किसी विशेष समूह/चिन्हित किए गए/एक साथ/समान मामलों में उपस्थिति को एक ही मामले में उपस्थिति के रूप में गणना किया जाएगा।

उपरोक्त आशय का प्रमाणन ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे चयन समिति द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय।

स्तम्भ-2**(एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम)**

5-भर्ती का स्रोत- सेवा में भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी:-

(ग) सीधी भर्ती द्वारा:

(1) आवेदन-पत्रों को प्रस्तुत किये जाने के लिए नियत अंतिम दिनांक को अन्यून सात वर्षों के लिये अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं में से:

परन्तु यह कि केवल ऐसे अधिवक्ता ही अर्ह होंगे जिन्होंने भर्ती के विज्ञापन के प्रकाशन वर्ष से पूर्व के अन्तिम तीन वर्षों में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष स्वतंत्र रूप से अन्यून निम्नलिखित मामलों का संचालन किया हो:-

(एक) अनारक्षित श्रेणियों के लिए 30;

(दो) इस नियमावली के अनुसार आरक्षण के हकदार अभ्यर्थियों के लिए 24;

स्पष्टीकरण:-किसी विशेष समूह/चिन्हित किए गए/एक साथ/समान मामलों में उपस्थिति को एक ही मामले में उपस्थिति के रूप में गणना किया जाएगा।

उपरोक्त आशय का प्रमाणन ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे भर्ती के प्रयोजनार्थ जारी विज्ञापन में अधिसूचित किया गया हो।

(2) उन न्यायिक अधिकारियों, जिन्होंने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रांतीय सिविल सेवा (न्यायिक) में भर्ती होने से पूर्व, एक अधिवक्ता/प्लीडर, जिसमें सरकारी प्लीडर और लोक अभियोजक सम्मिलित हैं, के रूप में सात वर्ष या उससे अधिक की निरंतर अभ्यास (प्रेक्टिस) पहले ही पूर्ण कर लिया हो, में से;

(3) कोई व्यक्ति जो न्यायिक सेवा में रहा हो या वर्तमान में हो और जिसके पास आवेदन जमा करने के अंतिम दिनांक तक एक अधिवक्ता और एक न्यायिक अधिकारी के रूप में सात वर्ष या उससे अधिक का संयुक्त और निरंतर अनुभव हो।

नियम 13 में उपनियम (3) का अर्थ:- 3- उक्त नियमावली में, नियम 13 में निम्नलिखित उपनियम (3) बढ़ा दिया जायेगा, बढ़ाया जाना

(3) उसी तरह, सेवारत न्यायिक अधिकारी और पूर्व न्यायिक अधिकारी, जो सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी हैं, उन्हें उस उच्च न्यायालय के महानिबंधक से, जहाँ वे सेवा में हैं या सेवा में थे, 'अच्छे चरित्र' का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

नियम 17 में उपनियम (4) का अर्थ:- 4- उक्त नियमावली में, नियम 17 में निम्नलिखित उपनियम (4) बढ़ा दिया जायेगा, बढ़ाया जाना

(4) नियम 5 (ग) के अधीन आवेदन करने वाले सेवारत न्यायिक अधिकारी और पूर्व न्यायिक अधिकारी अपना आवेदन सम्बंधित उच्च न्यायालय के महानिबंधक, जहाँ वे सेवा में हैं या सेवा में थे, के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

आज्ञा से,
एम0 देवराज,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 176/Two-4-2026-02-4003(002)/2-2025, dated May 5, 2026:

No. 176/Two-4-2026-02-4003(002)/2-2025

Dated Lucknow, May 5, 2026

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 read with Article 233 of the Constitution, the Governor in accordance with the recommendations of High Court of Judicature at Allahabad, is pleased to make the following Rules with a view to amend the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975:—

THE UTTAR PRADESH HIGHER JUDICIAL SERVICE
(NINETEENTH AMENDMENT) RULES, 2026

1. (i) These rules may be called "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service (Nineteenth Amendment) Rules, 2026". Short title and commencement

(ii) They shall come into force at once.

2. In the Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975, hereinafter referred to as the said rules, *for* existing Clause (c) of Rule 5 set out in column-1 below, the Rule as set out in column-2 shall be *substituted*, namely:— Substitution of Clause (c) in Rule 5

COLUMN-1

COLUMN-2

(Existing rule)

(Rule as hereby substituted)

Rule 5 Source of Recruitment -

The recruitment to the service shall be made:—

(c) By direct recruitment from amongst the advocates who have been in practice, for not less than seven years, as on the last date fixed for the submission of application forms:

Provided that only such advocates shall be eligible who have in the last three years from the year of publication of advertisement for recruitment, independently conducted cases, before any Court or Tribunal, not less than:—

(i) 30 for Unreserved categories;

(ii) 24 for candidates entitled to reservation as per these rules;

Explanation: Appearance in a particular bunch/tagged/ together/similar cases, shall be counted as appearance in one case.

The certification to the above effect shall be made by such authority as may be notified by the selection committee from time to time.

5. Source of Recruitment:-

The recruitment to the service shall be made:—

(c) By direct recruitment:

(I) from amongst the advocates who have been in practice, for not less than seven years, as on the last date fixed for the submission of application forms:

Provided that only such advocates shall be eligible who have in the last three years from the year of publication of advertisement for recruitment, independently conducted cases, before any Court or Tribunal, not less than:—

(i) 30 for Unreserved categories;

(ii) 24 for candidates entitled to reservation as per these rules;

Explanation: Appearance in a particular bunch/tagged/ together/similar cases, shall be counted as appearance in one case.

The certification to the above effect shall be made by such authority as may be notified in the advertisement issued for the purpose of recruitment.

(II) from amongst the Judicial Officers who have already completed seven years or more continuous practice as an Advocate/Pleader including Government pleaders and Public Prosecutors before being recruited in the Provincial Civil Service (Judicial) on the last date of submission of application;

(III) A person who has been or is in judicial service and has a combined and continuous experience of seven years or more as an Advocate and a Judicial Officer on the last date of submission of application.

Insertion of
sub-rule (3) in
Rule 13

3- In the said Rules, the following sub-rule (3) shall be *inserted* in Rule 13, namely:-

(3) Likewise, in service Judicial Officer and former Judicial Officer who is a candidate for direct recruitment must produce a certificate of good character from the Registrar General of the High Court where he/she is in service or was in service.

Insertion of
sub-rule (4) in
Rule 17

4- In the said Rules, the following sub-rule (4) shall be *inserted* in Rule 17, namely:-

(4) In service Judicial Officers and former Judicial Officers applying under rule 5(c) shall submit their applications through the Registrar General of the concerned High Court where they are in service or were in service.

By order,
M. DEVARAJ,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 112 राजपत्र-2026-(235)-599 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० नियुक्ति-2026-(236)-500 प्रतियां (डी०टी०पी०/आफसेट)।